

an>

Title: Demand to commence development programme and to make provision for reinforced cement concrete in Bihar.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति जी, धन्यवाद । मैं इस विषय को निरंतर इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़े राज्य का दर्जा दिया गया है और उसमें एक विषय सड़क का भी है । 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत बिहार को 6,000 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी गई और अभी बिहार सरकार से मात्र 1300 किलोमीटर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का दो तिहाई हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है और वहां की सड़कें टूटती रहती हैं ।

वर्तमान में कालीकरण का प्रस्ताव दिया जाता है, उससे सड़कें टूटती हैं और बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि हमें आरसीसी की सड़कें दी जाएं ताकि लंबी अवधि तक उन सड़कों का रख-रखाव हो सके । संकट यह है कि बिहार सरकार ने जिस प्रस्ताव को भेजा है और जो मानक प्राक्कलन भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, वह उस मानक में नहीं बैठता है । इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर यह पैसा कौन देगा? हम बिहार में कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है और मैं बार-बार सदन से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सबको बिहार की उपेक्षा को रोकना होगा और कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करना होगा । जहां तक यदि पूरे देश के विकास का सवाल है और अगर बिहार पिछड़ा हुआ रह जाता है तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इन्हीं मानकों से बिहार आज पिछड़ता जा रहा है । चाहे सड़कों का मानक हो, बिजली का मानक हो या फिर स्वास्थ्य का मानक हो । अगर हम एक-एक करके एक-एक क्षेत्र को छोड़ते जाएंगे तो फिर विकास का काम पूरा कैसे हो पाएगा? हम पांच-पांच, दस-दस साल से एक ही विषय को लेकर आ रहे हैं ।

महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक यह मानक बदला नहीं जाएगा और जब तक इन विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। इस सदन में पूरे भारतवर्ष के लोग बैठते हैं। हमारे बिहार के लोग पूरे भारतवर्ष में जाकर बसते हैं। इसका मूल रूप से यही कारण है कि वहां पर गरीबी है। हमारी कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारे यहां पर आप 300-400 किलोमीटर तक चले जाइए, वहां पर आपको एक भी फैक्ट्री का धुंआ नहीं मिलेगा। जब तक नीति नहीं बनेगी, तब तक निवेश नहीं आएगा। आखिर बिहार में नीति और निवेश का काम कौन करेगा? हमारे जैसे लोग, जो वर्षों से बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, उस पिछड़े राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उस पिछड़ेपन के लिए बिहार में निवेश की नीति होनी चाहिए और वह नीति तभी बनेगी, जब पूरा भारतवर्ष एक होकर बिहार के बारे में सोचना शुरू करेगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार के बारे में सदन को भी सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए ताकि हम बिहार के पिछड़ेपन पर इस बड़ी आवाज को उठा सकें।